दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 07 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 131

महत्वपूर्ण एवं खास

बीजेपी के तीन और नेताओं को मिली वाई+ सुरक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। गृह मंत्रालय ने भाजपा के 3 और नेताओं को वीआईपी सुरक्षा देने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि नेताओं को वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा के साथ सीआईएसएफ के कंमाडों भी साथ रहेंगे। केंद्र सरकार ने नलिन कोहली, ऋतुराज सिन्हा और अभय गिरी को सुरक्षा प्रदान की है। इन तीनों नेताओं के साथ अब भारी सुरक्षाबलों का काफिला रहेगा। जानकारी के अनुसार नगालैंड चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। नलिन कोहली भाजपा नगालैंड की स्टेट इंचार्ज है।

फ्लाईओवर पर टक्कर, दो की मौत

मेरठ (आरएनएस)। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व शोभापुर फ्लाईओवर से पहले हाईवे पर ऐसे ही एक जुगाड़ में जा रहे चार युवकों को उत्तराखंड बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बावजूद इसके हाईवे पर धड़ल्ले से ऐसे जुगाड़ चल रहे हैं। मगर ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों को सीज नहीं कर रही है।

ग्रीस में नौका डूबने से चार लोगों की मौत

एथेंस। यूनान के द्वीप लेरोस के तट पर प्रवासियों को ले जा रही एक नौका रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे तीन लडक़ों और एक महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नौका पर कम से कम 41 लोग सवार थे। यूनान के तटरक्षक बल के एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसने समुद्र में एक शव तैरता हुआ देखा है। इसके बाद मौके पर तीन पोत और एक विमान भेजा गया, जहां से एक महिला का शव मिला और एक बेसुध लडक़े समेत 39 लोगों वहां से निकाला गया। उन्होंने बताया कि बेसुध मिले लडक़े सहित दो और लडक़ों की रविवार शाम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं दोपहर में तीन नाबालिगों और दो व्यस्कों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाकी यात्री आश्रय शिविर में हैं। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तेज हवाएं चलने और बारिश के कारण नौका करीब आधी पानी में डूब गई थी।

दो दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का शुभारंभ

अजमेर (आरएनएस)। राजस्थान में अजमेर-जयपुर हाईवे स्थित कायड़ विश्राम स्थली पर आज से दो दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आगाज़ हुआ। शिविर का शुभारंभ झंडारोहण एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। अजमेर स्थित महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉ श्रीगोपाल बाहेती ने बताया कि शिविर में प्रतिभागियों को गांधी दर्शन से रुबरु कराया जाएगा जिसमें देश के ख्यातनाम गांधीवादी विचारक विचार व्यक्त करेंगे। उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता एवं चिंतक सतीश राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अनिल शुक्ला गांधी दर्शन पर अपने विचार रखेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में गांवों दर्शन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जाएगी।

आगरा में मेट्रो टनल का मुख्यमंत्री योगी ने किया शुभारंभ

आगरा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। रामलीला मैदान में लॉन्चिंग शाफ्ट पहुंचकर रिंग सेगमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद सीएम योगी ने पूजा-अर्चना करके बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया। आगरा में टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) को गंगा और यमुना का नाम दिया गया है। ये टनल बोरिंग मशीन हर दिन 10-12 मीटर तक टनल तैयार करेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप एवं डाउन ट्रैक के लिए दो समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। सीएम योगी ने अपने संक्षिप्त भाषण में आगरा को मिली मेट्रो रेल सौगात और जी 20 के आयोजनों के बारे में बताया। सीएम योगी ने कहा,मुझे उम्मीद है कि आगरा में निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। जी-20 देश के सबसे प्रतिष्ठित देशों का समूह है।

लंबी खींचतान के बाद सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के लगभग 2 महीने की खींचतान के बाद आखिरकार पांच जजों की नियुक्ति पर मोहर लग गई जिससे शीर्ष अदालत में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। उच्चतम न्यायालय के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। सोमवार को क्रमश: राजस्थान, पटना और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों-न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल और पीवी संजय कुमार के साथ पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने शपथ ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। यह समारोह अदालत के नए भवन में सभागार में आयोजित हुआ।

जस्टिस पंकज मिथल- जस्टिस पंकज मिथल राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे। वैसे उनका मूल कैडर इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। उनका ज्म 17 जून 1961 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने मेरठ कॉलेज से एलएलबी पूरी की। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्टर होकर वकील के रूप में प्रैक्टिस करने लगे। वह जम्मू-कश्मीर के चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।7 जुलाई 2006 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। 2008 में वह स्थायी जज बने।

जस्टिस संजय करोल- जस्टिस संजय करोल मूलत: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कैडर से हैं। वह पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1961 को हुआ था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई शिमला में की और इसके बाद शिमला के ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजे स्नातक पूरा किया। वह कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने हिमाचल विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ली। इसके बाद वकील के रूप में प्रैक्टिस करने लगे। 2007 में उन्हें हिमाचल हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था। वह त्रुपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी काम कर चुके हैं।

जस्टिस पीवी संजय कुमार- जस्टिस पीवी संजय कुमार मणिपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत थे। वह मूलत: तेलंगाना हाई कोर्ट कैडर के हैं। उन्होंने निजाम कॉलेज हैदराबाद से स्नातक पूं किया था। इसके बाद 1988 में दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। इसी साल उन्होंने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया। वह तेलंगाना के अडिशनल जज के तौर पर 2008 में पदोन्नत किए गए थे। वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी सेवा दे चुके हैं।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह- जस्टिस अमानतुल्लाह पटना हाई कोर्ट में सेवा देरहे थे। वह बिहार के ही रहने वाले हैं औऱ उन्होंने पटना लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अक्टूबर 2021 में उन्हें कुछ समय के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गाय ता। इसके बाद पिछले साल वह फिर से पटना हाई कोर्ट पहुंचे।

जस्टिस मनोज मिश्रा- जस्टिस मनोज मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटीस से कानून की डिग्री ली थी। इसके बाद हाई कोर्ट में वह प्रैक्टिस कर रहे थे। साल 2011 में उन्हें हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया था।

प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल किया लॉन्च

बेंगलुरू (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के कार्यक्रम के तहत 20 प्रतिशत इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल की शुरूआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्सर्जन और विदेशों पर निर्भरता को कम करना है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल में 10 फीसदी इथेनॉल मिलाया जाता है और 2025 तक एथेनॉल की मात्रा को दोगुना करने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 20 फीसदी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च करने के बाद कहा कि 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल 1.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है और अब यह बढक़र 20 फीसदी हो गया है।

सबसे पहले देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और आने वाले दो वर्षों में पूरे देश में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पंपों का विस्तार किया जाएगा। ईंधन आयात में 10 फीसदी की कमी कर देश ने 54,894 करोड़ रुपए की बचत की।

इथेनॉल-20 (20 प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल) 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा।

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने जून 2022 के दौरान पांच महीने पहले पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनॉल का सम्मिश्रण हासिल किया था और अब 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल निर्धारित समय से पहले पायलट आधार पर वितरित किया जाता है।

मध्य प्रदेश में रेल सुविधाएं बढ़ाने को मिले साढ़े 13 हजार करोड़

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश में रेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए यह अच्छी खबर है। राज्य के हिस्से में साढ़े 13 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल बजट 2023-24 में मध्यप्रदेश को राशि के आवंटन पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करते हुए कहा कि वर्ष 2009 से 2014 के औसत आवंटन 632 करोड़ रुपए से बढक़र वर्ष 2023-24 का आवंटन 13607 करोड़ रुपए है, जो 21.5 गुना अधिक है। इस बजट आवंटन से मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न रेल परियोजनाओं एवं अधो-संरचनात्मक कार्यों के साथ-साथ रेलवे के आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। मध्यप्रदेश में वर्तमान में 86 हजार 336 करोड़ रुपए की लागत के 40 रेल प्रोजेक्ट में 6,759 किलोमीटर के कार्य चल रहे हैं। राज्य में अमृत भारत स्टेशन स्कीम में मध्यप्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व-स्तरीय स्तर के बनाए जाने वाले है। वहीं भोपाल, सिंगरौली, खजुराहो, बीना, जबलपुर, सतना और उज्जैन रेलवे स्टेशन का टेक्नो इकानॉमिक्स फिजिबिलिटि अध्ययन शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2014 से 971 रेल फ्लाई ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करवाया गया। वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट के स्टॉल 47 रेलवे स्टेशन पर खोलने की योजना है। उल्लेखनीय है कि 100 करोड़ की लागत से भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का विकास किया जा चुका है। साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिये 535 करोड़ रुपए का टेण्डर पारित हो चुका है।

आईटीआई पास युवा रोजगार के लायक नहीं : आईटीआई पास करने वाले युवाओं को लेकर नीति आयोग ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली (आरएनएस)। आईटीआई पास करने वाले युवाओं को लेकर नीति आयोग ने बड़ा खुलासा किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मानक के अनुसार नहीं हैं। आईटीआई भारत में व्यावसायिक प्रशिक्षण की रीढ़ हैं। हर साल लाखों छात्र आईटीआई में दाखिला लेते हैं, लेकिन फिर भी यह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, फैकल्टी और बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों के अनुरूप नहीं है।

ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स शीर्षक से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने कहा है कि आईटीआई पास करने वाले युवा न तो रोजगार योग्य हैं और न ही अपना उद्यम शुरू करने के लिए पर्याप्त कुशल हैं। कई बार आईटीआई का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया गया। जिसमें उत्कृष्टता केंद्र बनाना, फंडिंग, आईटीआई की ग्रेडिंग और आईएमसी को अनिवार्य बनाना इत्यादि शामिल है लेकिन इसके बावजूद आईटीआई का पूरा सिस्टम सिर्फ मुश्किलों का सामना कर रहा है।

देशभर में आईटीआई में 25 लाख सीटें हैं, लेकिन मात्र 10.5 लाख सीटें ही भर रही हैं। प्लेसमेंट की दर और भी निराशाजनक है। आईटीआई की गुणवत्ता और सामाजिक स्वीकार्यता कम है। देश के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवित करने के लिए नीति आयोग के स्किल डेवलपमेंट एंड एंप्लॉयमेंट वर्टिकल द्वारा अध्ययन किया गया है। इसमें कई सुझाव भी दिए गए हैं।

देशभर में मौजूद आईटीआई में 78.40 फीसदी निजी लोगों द्वारा चलाए जाते हैं। बचे हुए 21.59 फीसदी सरकारी संस्थान हैं। सरकारी संस्थानों में निजी की तुलना में ज्यादा छात्र नामांकित हैं। जबकि 62 फीसदी सीटें निजी संस्थानों में ही हैं।

देश में अभी कुल 14789 आईटीआई हैं। इनमें 66 फीसदी संस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इन पांच राज्यों में ही हैं। इनमें 64.81 फीसदी सीटें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की खाली हैं। 71.57 फीसदी सीटें फीटर ट्रेड में खाली हैं।

अडाणी समूह के मुद्दे पर विपक्ष का लोकसभा में हंगामा

❐ कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

नई दिल्ली (आरएनएस)। अडाणी समूह से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन में आज भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह पर 'हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और शेयर बाजार में उससे जुड़े घटनाक्रम के मुद्दे पर जांच के लिए जेपीसी गठित करने तथा इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न दो बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। इसी दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गये। सभापति ने सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कार्यवाही चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी विपक्षी सदस्यों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने देने की अपील करते हुए कहा कि सदस्य (अडाणी मुद्दे पर) जो बोलना चाहें, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोल सकते हैं। उन्होंने कहा, 'संसद की परंपरा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सबसे पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सदस्य चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। इस विषय पर वित्त मंत्री को जो कहना था, सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं।' जोशी ने कहा कि संसद का समय बहुमूल्य है, इसलिए सदस्यों को अपने स्थान पर जाकर चर्चा शुरू करानी चाहिए और सरकार उत्तर देने को तैयार है। हालांकि हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति सोलंकी ने कुछ ही मिनट बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों ने शोर-शराबा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की। उन्होंने श्रम मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न के लिए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का नाम पुकारा, हालांकि विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। बिरला ने कहा, 'आज मजदूरों से जुड़ा प्रश्न है...यह सदन की दिशा तय करता है। आपको किसी विषय पर चर्चा करनी है तो बातचीत करें। आप बिना बातचीत के, केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराएं, यह उचित नहीं है। आप मेरे कक्ष में आएं, बातचीत करें, किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दूंगा। बिरला ने कहा, 'नारेबाजी करना जनता के हित में नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों से जुड़ा सवाल उठाने दीजिए। आपने (कांग्रेस) लंबे समय तक राज किया है। आप इतनी पुरानी पार्टी हैं, यह व्यवहार उचित नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर लोकसभा अध्यक्ष ने करीब 11 बजकर पांच मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसी विषय पर गत सप्ताह भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी।

कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसे हालात, 25 घरों में आई दरारें, 8 घरों को किया असुरक्षित घोषित

चमोली (आरएनएस)। जोशीमठ में हो रहे भू-धंसाव के बाद सरकार इलाके में आपदा से निपटने की तैयारी में लगी हुई है। तो वहीं कर्णप्रयाग में भी अब जोशीमठ जैसे हालत बनते हुए दिख रहे हैं। कर्णप्रयाग में भी जिन घरों में दरारें आई है वो ओर ज्यादा चौड़ी हो गई है। यहां भी करीब 25 घरों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। जिसमें से आठ घर रहने लायक नहीं बचे हैं। प्रशासन ने इन आठ इमारतों को असुरक्षित घोषित कर दिया। वहीं, प्रभावित परिवारों ने भवन खाली कर दिए, उन्हें कर्णप्रयाग नगर पालिका के रैन बसेरों में स्थानांतरित कर दिया गया। तहसीलदार सुरेंद्र देव का यह भी कहना है कि मकान खाली करने के बाद सभी प्रभावित परिवारों को नगर पालिका के रैन बसेरों और आईटीआई कॉलेज की कक्षाओं में स्थानांतरित कर दिया गया है। इनमें से आठ परिवारों को जनवरी में शिफ्ट किया गया था। कर्णप्रयाग के बहुगुणानगर में घरों में दरारें आने से 38 परिवार प्रभावित हुए हैं।

इसके साथ ही प्रशासन और एक्सपर्ट की संयुक्त टीम ने भी बदरीनाथ हाईवे के पास स्थित आईटीआई क्षेत्र के बहुगुणा नगर और सब्जी मंडी ऊपरी हिस्से में भू-धंसाव से क्षतिग्रस्त हुए भवनों का निरीक्षण किया, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

तुर्की, सीरिया में भीषण भूकंप में 1300 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों इमारतें जमींदोज

अंकारा । दक्षिणपूर्वी तुर्की और सीरिया में सोमवार तडक़े 7.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें ढह गईं। भूकंप संबंधी घटनाओं में कम से कम 1300 लोगों की मौत की खबर है। मृतक संख्या के बढऩे की आशंका है क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। आंशिक रूप से ढह गई इमारतों के अंदर फंसे लोग व सडक़ पर मौजूद लोग मदद की गुहार लगाते नजर आए। भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। इसका केंद्र सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर में गजियांतेप शहर के उत्तर में था। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने ट्वीट किया कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए 'तलाश एवं बचाव दलों को तुरंत रवाना कर दिया गया है। भूकंप के बाद करीब 6 झटके महसूस किए गए।

गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने लोगों से क्षतिग्रस्त इमारतों में जाने से बचने को कहा है। उन्होंने कहा, 'हमारी प्राथमिकता इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालना और उन्हें अस्पताल पहुंचाना है। तुर्की के मालात्या प्रांत के गवर्नर हुलुसी साहिन ने बताया कि कम से कम 130 इमारतें ढह गईं। दियारबाकिर शहर में कम से कम 15 इमारतें ढह गईं। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्ष के 'सीरियन सिविल डिफेंस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति को ''विनाशकारी बताते हुए कहा कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं। 'सीरियन सिविल डिफेंस ने लोगों से इमारतों से बाहर खुले स्थान पर रहने को कहा है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप का केंद्र गजियांतेप से करीब 33 किलोमीटर दूर 18 किलोमीटर की गहराई पर था। प्रांतों में इसके झटके महसूस किए गए। भूकंप ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम एशिया बर्फीले तूफान की चपेट में है जिसके बृहस्पतिवार तक जारी रहने के आसार हैं। उत्तर-पश्चिम तुर्किये में 1999 में आए शक्तिशाली भूकंप में करीब 18,000 लोग मारे गए थे।

तुर्की में भूकंप से भारी तबाही के बीच मदद भेजेगा भारत

नई दिल्ली (आरएनएस)। तुर्की में आए भूकंप से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने तत्काल राहत उपायों पर चर्चा करने के लिए साउथ ब्लॉक में एक बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि तुर्की गणराज्य की सरकार के समन्वय से राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा दलों के खोज और बचाव दलों को तुरंत वहां भेजा जाएगा। इस उच्चस्तरीय बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय, एनडीएमए, एनडीआरएफ, रक्षा, विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बचाव दलों को तुर्की भेजने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वॉड और आवश्यक उपकरणों के साथ 100 कर्मियों वाली एनडीआरएफ की दो टीमें खोज और बचाव कार्यों के लिए भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टरों के साथ मेडिकल टीमें भी तैयार की जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक तुर्की गणराज्य की सरकार और अंकारा में भारतीय दूतावास और इस्तांबुल में महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय के समन्वय से राहत सामग्री भेजी जाएगी। गौरतलब है कि दक्षिणपूर्वी तुर्की और सीरिया में सोमवार को तडक़े 7.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे कई इमारतें ढह गईं।